



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2000/भाद्र 8, 1922

No. 563]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2000/BHADRA 8, 1922

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2000

का. आ. 784(अ).—केंद्रीय सरकार ने वर्तमान में उपयोग किए जा रहे कार्बोफेन्थीन नाशकमात्र का पुनरीक्षण करने के लिए और भारत में उनका उपयोग जारी रखा जाए या नहीं पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था :

केंद्रीय सरकार का, उक्त विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने और वरीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि कार्बोफेन्थीन 50% जल विलेय चूर्ण के उपयोग में मनुष्या और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए परिसकट अंतर्द्विलित है :

अतः अब केंद्रीय सरकार वरीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 26 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित प्रारूप आदेश करने का प्रस्ताव करती है अर्थात् :-

प्रारूप आदेश

केंद्रीय सरकार की यह राय है कि कार्बोफेन्थीन 50% जल विलेय चूर्ण के उपयोग में मनुष्या और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए परिसकट अंतर्द्विलित है और अतः यह प्रस्ताव करती है कि उक्त नाशकमात्र के विनाशकारी उपयोग पर इस आदेश के राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से पूर्णतया पाबंदी होगी ।

कार्बोफुरान 50% जल विलेय घूर्ण के उत्पादन के लिए नए रजिस्ट्रीकरण या विनिर्माण अनुज्ञप्ति पर पाबंदी होगी ।

कार्बोफुरान 50% जल विलेय घूर्ण के विभिन्न रजिस्ट्रीकर्ताओं को विनिर्माण एकाई के स्थापित किए जाने के लिए जारी की गई विनिर्माण अनुज्ञप्तियां उन फर्मों या व्यक्तियों की बाबत रद्द कर दी जाएगी ।

कार्बोफुरान 50% जल विलेय घूर्ण की बाबत ऐसे रजिस्ट्रीकर्ताओं के संबंध में जिन्होंने अभी तक विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने का प्रस्ताव है ।

राज्य सरकार अपनी-अपनी अधिकारिता में ऐसे उपाय करने के लिए सशक्त होगी जो वह इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए ठीक समझे ।

प्रारूप आदेश, जो केंद्रीय सरकार करने का प्रस्ताव करती है ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप आदेश पर उस तारीख से जिस तारीख को उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह आदेश समाविष्ट है जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा ;

कोई व्यक्ति जो उक्त प्रारूप आदेश की बाबत सुझाव देन या आक्षेप करने का इच्छुक हो वह उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेज सकता है ।

[फा. सं. 17-2/98-पौ. स.-1]

पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)
ORDER

New Delhi, the 30th August, 2000

S.O. 784(E).— Whereas the Central Government had set up an Expert Group to undertake review of certain pesticides in use at present and to consider their continued use or otherwise in India;

And whereas the Central Government after considering the recommendations of the said Expert Group and after consultation with the Registration Committee set up under the Insecticides Act, 1968 is satisfied that the use of Carbofuran 50% Water Soluble Powder (SP) involves health hazards to human beings and animals;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby proposes to make the following draft Order, namely:-

Draft Order

Whereas the Central Government is of the opinion that the use of Carbofuran 50% Water Soluble Powder (SP) involves health hazards to human beings and animals and therefore, proposes that the manufacture and use of the said pesticide shall be banned completely from the date of the final publication of this Order in the Official Gazette.

There shall be a ban on new registration or manufacturing license for production of Carbofuran 50% Water Soluble Powder (SP).

The manufacturing licenses issued to various registrants of Carbofuran 50% Water Soluble Powder (SP) for setting up of manufacturing units shall be cancelled in respect of those firms or persons.

It is proposed to cancel the Certificate of registration in respect of Carbofuran 50% Water Soluble Powder (SP) in respect of those registrants who are yet to obtain manufacturing licenses.

The State Government shall be empowered to take all such steps in their respective jurisdiction as it may deem fit for carrying out this Order.

The draft Order, which the Central Government proposes to make, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft Order shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are made available to the public;

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft Order may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation), Krishi Bhavan, New Delhi-110001.

आदेश

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2000

का. आ. 785(अ).— केंद्रीय सरकार ने वर्तमान में उपयोग किए जा रहे कतिपय नाशकमारों का पुनरीक्षण करने के लिए और भारत में उनका उपयोग जारी रखा जाए या नहीं पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था ;

केंद्रीय सरकार का, उक्त विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने और कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि शुष्क बीज उपचार के लिए कैप्टाफोल 80 प्रतिशत चूर्ण के उपयोग में मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए परिसंकट अंतर्वलित है :

अतः अब केंद्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित प्रारूप आदेश करने का प्रस्ताव करती है अर्थात् :-

प्रारूप आदेश

केंद्रीय सरकार की यह राय है कि शुष्क बीज उपचार के लिए कैप्टाफोल 80 प्रतिशत चूर्ण उपयोग में मनुष्यों, पशुओं और वातावरण के स्वास्थ्य के लिए परिसंकट अंतर्वलित है और अतः यह प्रस्ताव करती है कि उक्त नाशकमार के विनिर्माण पर इस आदेश के राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से पूर्णतया पाबंदी होगी और इसका उपयोग, राजपत्र में इस आदेश के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि या इस आदेश की समाप्ति जा भी पहले हो, प्रतिषिद्ध होगा ।

निर्माण केवल निर्यात के प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा और इस शर्त के अधीन होगा कि यह क्रियाकलाप, बन्द प्रणाली में किया जाए जिससे कि कारखाना कर्मचारियों को उच्छन्न होने से बचाया जा सके ।

राज्य सरकार अपनी-अपनी अधिकारिता में ऐसे उपाय करने के लिए सशक्त होगी जो वह इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए ठीक समझे ।

प्रारूप आदेश, जो केंद्रीय सरकार करने का प्रस्ताव करती है ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप आदेश पर उस तारीख से जिस तारीख का उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह आदेश समाविष्ट है, जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा :

काई व्यक्ति जो उक्त प्रारूप आदेश की बाबत सुझाव देने या आपक्ष करने का इच्छुक हो वह उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भज सकता है ।

ORDER

New Delhi, the 30th August, 2000

S.O. 785(E).— Whereas the Central Government had set up an Expert Group to undertake review of certain pesticides in use at present and to consider their continued use or otherwise in India;

And whereas the Central Government after considering the recommendations of the said Expert Group and after consultation with the Registration Committee set up under the Insecticides Act, 1968 is satisfied that the use of captafol 80% powder for dry seed treatment (DS) involves health hazards to human beings, animals and environment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby proposes to make the following draft Order, namely:-

Draft Order

Whereas the Central Government is of the opinion that the use of captafol 80% powder for dry seed treatment (DS) involves health hazards to human beings, animals and environment and therefore, proposes that the manufacture of the said pesticide shall be banned completely from the date of the final publication of this Order in the Official Gazette and its use shall be prohibited from the date of its expiry or the period of two years from the date of final publication of this Order in the Official Gazette, whichever is earlier.

The manufacture shall continue for export purposes only subject to the condition that this activity is handled in a closed system so as to avoid any exposure to factory workers.

The State Government shall be empowered to take all such steps in their respective jurisdiction as it may deem fit for carrying out this Order.

The draft Order, which the Central Government proposes to make, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft Order shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are made available to the public;

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft Order may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation), Krishi Bhavan, New Delhi-110001.

[F. No. 17-2/98-PP-I]
P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2000

का. आ. 786(अ).— केंद्रीय सरकार ने वर्तमान में उपयोग किए जा रहे कतिपय नाशकमारी का पुनरीक्षण करने के लिए और भारत में उनका उपयोग जारी रखा जाए या नहीं पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था :

केंद्रीय सरकार का, उक्त विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने और कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि फल और सब्जियों पर मिथाइल पाराथ्रियॉन की विनिर्मितियों के उपयोग में मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए परिसंकट अतर्वर्तित है :

अतः अब केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा, 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित प्रारूप आदेश करने का प्रस्ताव करती है, अर्थात् :-

प्रारूप आदेश

केंद्रीय सरकार की यह राय है कि फल और सब्जियों पर मिथाइल पाराथियोन की 2 प्रतिशत धूलनीय चूर्ण और 50 प्रतिशत पायसनीय सान्द्र विनिर्मितियों के उपयोग में मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए परिसंकट अंतर्वलित है और अतः यह प्रस्ताव करती है कि उक्त नाशकमार के फल और सब्जियों पर उपयोग पर इस आदेश के राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से पूर्णतया पाबंदी होगी ।

मिथाइल पाराथियोन के ऐसे रजिस्ट्रीकर्ताओं के संबंध में, जो इस आदेश के अनुसार पात्र के साथ उपान्वित लेबल और पर्णक प्रदान नहीं करते, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने का प्रस्ताव है ।

राज्य सरकार अपनी-अपनी अधिकारिता में ऐसे उपाय करने के लिए सशक्त होगी जो वह इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए ठीक समझे ।

प्रारूप आदेश, जो केंद्रीय सरकार करने का प्रस्ताव करती है ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप आदेश पर उस तारीख से जिस तारीख को उस राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह आदेश समाविष्ट है, जनता को उपलब्ध कराई जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा ।

कोई व्यक्ति जो उक्त प्रारूप आदेश की बाबत सुझाव देने या आपक्ष करने का इच्छुक हो वह उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेज सकता है ।

[फा. सं. 17-2/98-पौ. स.-I]

पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 30th August, 2000

S.O. 786(E).— Whereas the Central Government had set up an Expert Group to undertake review of certain pesticides in use at present and to consider their continued use or otherwise in India;

And whereas the Central Government after considering the recommendations of the said Expert Group and after consultation with the Registration Committee set up under the Insecticides Act, 1968 is satisfied that the use of formulations of Methyl Parathion on fruits and vegetables involves health hazards to human beings and animals;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby proposes to make the following draft Order, namely:-

Draft Order

Whereas the Central Government is of the opinion that the use of 2% Dustable Powder (DP) and 50% Emulsifiable Concentrate (EC) formulations of Methyl Parathion on fruits and vegetables involves health hazards to human beings and animals and therefore, proposes that the use of the said pesticide shall be banned completely on fruits and vegetables from the date of the final publication of this Order in the Official Gazette.

It is proposed to cancel the registration certificate of formulations of Methyl Parathion in respect of those registrants who do not provide modified labels ^{on} leaflets along with container as per this Order.

The State Government shall be empowered to take all such steps in their respective jurisdiction as it may deem fit for carrying out this Order.

The draft Order, which the Central Government proposes to make, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft Order shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are made available to the public;

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft Order may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation), Krishi Bhavan, New Delhi-110001.

[F. No. 17-2/98-PP-I]
P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.